हमारा समाज हमेशा असमानताओं से भरा रहा है। यह एक जाति विहीन, स्तरीकृत श्रेणीबद्ध समाज था, और समाज के एक विशेष वर्ग को नंगे मानव जाति से वंचित कर दिया गया था ...।

"सुरक्षात्मक भेदभाव"

हमारा समाज हमेशा असमानताओं से भरा रहा है। यह एक जाति विहीन, स्तरीकृत श्रेणीबद्ध समाज था, और समाज के एक विशेष खंड को नंगे मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उनकी शिक्षा, मजदूरी, रहन-सहन, सामाजिक स्थिति समाज के ऊपरी तबके के स्वामियों द्वारा तय की गई थी, जो उन्हें कम कर देती है। आर्थिक पिछड़ेपन ने सामाजिक अजीबता ला दी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नीचा दिखाया गया और इस तरह उन्हें जीवन की गरिमा से भी वंचित कर दिया गया। जाति के आधार पर संकलित समाज में, उच्च जातियों ने सत्ता के लीवरों को नियंत्रित किया ताकि वे अपने कोड़ा चलाने में सक्षम हो सकें, जो समाज के निचले वर्गों के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। निचली जातियों को बिना किसी कहे और शिकायत निवारण तंत्र के सवर्णों की सेवा करनी थी। सदियों से चली आ रही यह अमानवीय और बर्बर स्थिति
"

कोई भी लोकतांत्रिक समाज दो अनिवार्य रूप से विरोधाभासी राजनीतिक अवधारणाओं के सामंजस्य की चुनौती का सामना करता है - एक, धर्म, जाति, नस्ल, नस्ल और लिंग के बावजूद कानून के समक्ष समानता, और दूसरा, समानता से पहले समान प्रतिबद्धता की कीमत पर सामाजिक न्याय। कानून। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा

Scanned with CamScanner

की कीमत पर सामाजिक न्याय। कानून। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विकसित लोकतंत्र भी नियम का कोई अपवाद नहीं है और कानून से पहले सभी नागरिकों की व्यक्तिगत योग्यता और समानता की कीमत पर समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए सहारा लिया है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने जाति व्यवस्था नामक अपने अजीबोगरीब संस्थान के कारण सदियों से सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया है, इन कम-विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए निवारण प्रदान करने का प्रयास किया गया है,

सभी में, चार अंडर-विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों को या तो योजना के तहत लाभ मिला है या वे इस तरह के लाभों की मांग कर रहे हैं, अर्थात् अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), धार्मिक अल्पसंख्यक या वर्ग तत्संबंधी, और हाल ही में, महिलाएं। यह परियोजना राजनीतिक दृष्टिकोण से इन श्रेणियों पर चर्चा करती है। हालाँकि, इसका दायरा संचालन के साथ-साथ विचाराधीन दोनों योजनाओं का आकलन करने तक सीमित है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर। विभिन्न राज्यों के अनुभवों को केवल उदाहरण देने या किसी विशेष बिंदु को बनाने के लिए कभी-कभी संदर्भित किया जाता है।

अर्थ और पृष्ठभूमि

सुरक्षात्मक भेदभाव, विशेष रूप से दलित और समाज के वंचित वर्गों को विशेष रूप से महिलाओं को विशेष विशेषाधिकार देने की नीति है। ये सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम हैं,

Scanned with CamScanner

जो संयुक्त राज्य और भारत दोनों में सबसे अधिक दिखाई देते हैं, जहां नस्लीय और जातिगत भेदभाव का इतिहास रहा है। यह प्रथा भारत में सबसे प्रमुख है, जहां इसे संविधान में संस्थागत रूप दिया गया है।

सामाजिक रूप से वंचितों के पक्ष में सकारात्मक रूप से भेदभाव करने की आवश्यकता को पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान महसूस किया गया था। यह महात्मा गांधी थे, जो खुद एक कट्टर हिंदू और जाति व्यवस्था में कट्टर विश्वास रखने वाले थे, जो इस विषय के महत्व को महसूस करने वाले और पूरे समुदायों को फिर से शिक्षित करने के लिए इस सदियों पुरानी सामाजिक कुरीतियों के लिए उच्च जातियों की अंतरात्मा की आवाज बुलंद करने वाले पहले नेता थे। "अछूत" की अपमानजनक स्थिति के लिए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए लोगों के इस बड़े निकाय को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल करने के राजनीतिक तर्क को भी समझा। इन अछूतों को "हरिजनों" (ईश्वर के लोगों) के रूप में नाम देकर उन्होंने इस नीति को एक धार्मिक स्वीकृति देने की कोशिश की ताकि जाति के हिंदुओं की पारंपरिक संवेदनशीलता से अधिक परेशान न करें, यह वास्तव में आवश्यक था।

स्वतंत्र भारत का संविधान, जो काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पैटर्न का पालन करता था, ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के प्रावधान किए, जो विभाजित भारत की आबादी का लगभग 23% था। उनके लिए संसदीय सीटों को आरक्षित करने के अलावा, उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में

Scanned with CamScanner

और कॉलेजों में प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों, उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न आर्थिक लाभ, और इसी तरह के लाभ दिए गए।

कुछ संवैधानिक प्रावधान जिनका उद्देश्य सकारात्मक भेदभाव है:

अनुच्छेद 17: "अस्पृश्यता" का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका अभ्यास एक दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 46: शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 16 और 335: सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के मामलों में अधिमान्य उपचार।
330 और 332: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण।

बाद में, नौकरी से संबंधित सकारात्मक भेदभाव को सरकार समर्थित स्वायत्त निकायों तक बढ़ाया गया। 1974 के एक सरकारी आदेश ने यह निर्धारित किया कि ऐसे सभी निकाय जो 20 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, और जहाँ आवर्ती व्यय का 50% केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए मिलता है, और जिसे वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए कम से कम रु। 200,000 का प्रावधान होना चाहिए। जिस सामान्य नियम ने वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को सकारात्मक भेदभाव के दायरे से बाहर रखा, वह स्वायत्त निकायों पर भी लागू था।

रिकार्ड

अनुसूचित जातियों और जनजातियों

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जातियों और जनजातियों

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान भारत के संविधान में इस प्रकार किया गया है: -

अनुच्छेद 16 (1): राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16 (4): अनुच्छेद 16 राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के लिए प्रदान करता है, फिर भी, "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेंगे या किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं"।

अनुच्छेद 16 (4) में दो संविधान संशोधन शामिल किए गए हैं, वे हैं: -

अनुच्छेद १६ (४-ए): इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकता है, परिणामी वरिष्ठता के साथ, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व द्वारा पर्याप्त नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देते हुए संविधान में 77 वां संशोधन लाया गया है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार, संविधान में संशोधन करके, संसद ने इंदिरा साहनी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के आधार को हटा दिया है कि नियुक्ति में पदोन्नति शामिल नहीं है। अनुच्छेद 16 (4 ए) इस प्रकार अनुच्छेद 16 पर लगाई गई व्याख्या को पुनर्जीवित करता है। आरक्षण का नियम न केवल प्रारंभिक भर्तियों पर बल्कि पदोन्नति पर भी लागू हो सकता है। लेकिन ओबीसी के लिए पदोन्नति पदों में कोई पदोन्नति नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है कि अनुच्छेद 16 (4 ए) को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि नियुक्तियों के मामले में आरक्षित वर्गों के साथ-साथ समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी उचित अवसर पैदा हो।

अनुच्छेद 16 (4-बी): "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को उस वर्ष के किसी भी अधूरे रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगा, जो क्लॉज (4) या क्लॉज के तहत किए गए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित हैं। (4 ए) किसी भी सफल वर्ष या वर्षों में भरे जाने वाले रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में और रिक्तियों के ऐसे वर्ग को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें उन्हें पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर आरक्षण। "

संविधान (अस्सी - पहला संशोधन) अधिनियम, 2000 ने संविधान में अनुच्छेद 16 (4 बी) जोड़ा है। संशोधन की परिकल्पना की गई है कि अपूर्ण आरक्षित रिक्तियों को

Scanned with CamScanner

की गई है कि अपूर्ण आरक्षित रिक्तियों को बाद के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाए और इन रिक्तियों को किसी वर्ष के दौरान वर्तमान रिक्तियों से अलग और अलग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण का नियम केवल सामान्य रिक्तियों पर लागू होना है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी सीमा के अपूर्ण आरक्षित रिक्तियों को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकता है, और सामान्य रिक्तियों से अलग भरा जाना चाहिए। यह संशोधन इंदिरा साहनी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव को भी संशोधित करता है।

अनुच्छेद 335: यह लेख प्रदान करता है कि "संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों की व्यवस्था में प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ-साथ एससी और एसटी के सदस्यों के दावों पर ध्यान दिया जाएगा। एक राज्य का "।

भारत में पिछड़े वर्गों
के लिए आरक्षण राज्य के अधीन। यहाँ राज्य शब्द केंद्र और राज्य सरकारों और उनके वाद्य यंत्रों दोनों को दर्शाता है।

राज्य पर दी गई शक्ति का उपयोग केवल एक पिछड़े वर्ग के पक्ष में किया जा सकता है और इसलिए, क्या नागरिकों का एक विशेष वर्ग पिछड़ा है, राज्य द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एक उद्देश्य कारक है।

यह जम्मू और कश्मीर राज्य के टी रिलोकी नाथ बनाम राज्य में आयोजित किया गया था , राज्य का निर्धारण न्यायसंगत होना चाहिए और अगर यह अप्रासंगिक विचारों पर

Scanned with CamScanner

, राज्य का निर्धारण व्यक्तिपरक होना चाहिए और अगर यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित हो तो चुनौती दी जा सकती है।

में **मोहन कुमार सिंघानिया v। भारत संघ**, अनुच्छेद 16 (4) की प्रकृति की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य के किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई प्रावधान या आरक्षण देने के लिए राज्य पर एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने वाला एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य की राय में पर्याप्त रूप से नहीं है राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व किया। अनुच्छेद 16 (4) न तो किसी संवैधानिक कर्तव्य को लागू करता है और न ही आरक्षण का दावा करने के लिए किसी पर कोई मौलिक अधिकार देता है। राज्य सरकार पिछड़े वर्ग की कुल आबादी और राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को लेती है और आवश्यक अभ्यास करने के बाद आरक्षण करती है और पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत प्रदान करती है, फिर प्रतिशत का सख्ती से पालन करना पड़ता है।

क्या हैं "पिछड़े वर्ग U / Art। संविधान का 16 (4)?

राष्ट्र में भारी बहुमत था जो अभी भी पिछड़ा हुआ था - सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से। पिछड़े हुए पिछड़ेपन के शिकार में वर्तमान अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शामिल हैं। भले ही, ये वर्ग उदारतापूर्वक "पिछड़ा वर्ग" हैं, लेकिन उनके पिछड़ेपन की प्रकृति और परिमाण समान नहीं हैं।

अनुच्छेद 16 (4) में होने वाले "पिछड़े वर्ग के नागरिक" शब्द संविधान में हालांकि न तो परिभाषित और न ही व्याख्यायित हैं।

Scanned with CamScanner

परिभाषित और न ही व्याख्यायित हैं। अनुच्छेद 15 (4) में होने वाले समान शब्द एक योग्य वाक्यांश, "सामाजिक और शैक्षिक रूप से" पिछड़े वर्गों द्वारा पीछा किए जाते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) की मंशा पर संसद में बहस के दौरान डॉ। बीआर अंबेडकर,पिछड़ा वर्ग "कुछ और नहीं बल्कि कुछ जातियों का एक संग्रह है।

संयोग से, यह बताना भी आवश्यक है कि आरक्षण पर अपने सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4) में "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से" पिछड़े होने की अभिव्यक्ति `पिछड़े वर्ग 'की व्याख्या की है। इसने अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण की एकमात्र या प्राथमिक कसौटी के रूप में "आर्थिक पिछड़ेपन" को सशक्त रूप से खारिज कर दिया और कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन का कारण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। इस अभिव्यक्ति का सही अर्थ बालाजी से इंदिरा साहनी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए कई मामलों में माना गया है।

Scanned with CamScanner